स्वच्छ भारत
सम्पूर्ण स्वच्छता की ओर

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

स्वच्छता समाचार

अगस्त 2024

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण

@swachhbharat @SBMGramin @SwachhBharatMissionGramin @swachhbharatgrameen

"जल शक्ति मंत्री के रूप में, मुझे अब तक की गई उल्लेखनीय प्रगति को स्वीकार करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) से महिलाओं और बच्चों सहित लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। हम इस सफलता को आगे बढ़ाते रहेंगे और परिवर्तनकारी पहल की प्राथमिकता भी तय करेंगे जो जल प्रबंधन और स्वच्छता में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और सामुदायिक सहभागिता का उपयोग करती हैं। हमारी प्रतिबद्धता भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए स्थायी, स्वच्छ जल की सुविधा और उन्नत स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करना है। साथ मिलकर, नई कार्यनीतियों का नेतृत्व करके और व्यावहारिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर, इससे हमारे देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।"

श्री सी. आर. पाटिल
केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

कार्यक्रम की उपलब्धियां

31 जुलाई, 2024 तक

ODF PLUS

भारत के **5.48 lakh** से अधिक बसे हुए गांवों ने स्वयं को ODF Plus घोषित किया है।

- उदीयमान: **2,72,686**
- उज्ज्वल: **34,905**
- उत्कृष्ट: **2,41,086**
- सत्यापित: **74,013**

3,59,710 गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है
4,87,645 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है
1126 बायोगैस संयंत्र पंजीकृत
734 कार्यशील बायोगैस संयंत्र
77 कार्यपूर्ण बायोगैस संयंत्र
3412 ब्लॉकों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है

स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियां (जुलाई, 2024)

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 जुलाई 2024 को शास्त्री भवन में स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दिया, जिसके कारण पिछले दशक में ग्रामीण और शहरी भारत में लगभग 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। उन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा पहल के महत्व को व्यापक स्वच्छ भारत का एक अभिन्न अंग के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने सभी विभागों में स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और मंत्रालय के तहत संबद्ध कार्यालयों सहित सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी पर प्रकाश डाला।
उन्होंने पिछले वर्ष की स्वच्छता पखवाड़ा की उपलब्धियों पर विचार व्यक्त किया जिसमें पखवाड़ा में स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण, स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना और सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यालयों में सफाई अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल रहीं। ये सभी सतत विकास लक्ष्य 6 (एसडीजी-6) को प्राप्त करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन, जो मिशन की शुरुआत में लगभग न के बराबर था, अब प्रभावशाली 77 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

और अधिक पढ़ने के लिए यहां **क्लिक करें**

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

HPCL: अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए जूते-चप्पल वितरित करना; विरासत स्थलों के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाना।

GAIL: वृद्धाश्रमों में व्यक्तिगत स्वच्छता सामग्री का वितरण; सभी कर्मचारियों को पौधों का वितरण।

ONGC: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा वाटर कूलर का उद्घाटन, पुनर्चक्रित प्लास्टिक बेंच, बाजरा के पैकेट, फूलों के बीज और जूट के बैग का वितरण।

IOCL: विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और स्वच्छता रथ द्वारा स्वच्छता अभियान का उद्घाटन किया गया।

NRL: छात्रों के बीच स्वच्छता जागरूकता सत्र के बाद स्वच्छता अभियान चलाया गया।

GAIL: स्वच्छता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक/स्ट्रीट प्ले और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। सफाई साथियों की पहचान और चिकित्सा शिविरों के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य जांच करना

MRPL: महिलाओं के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किए गए, जिसमें एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक लगाने के महत्व पर चर्चा की गई और 4 आर को बढ़ावा देने के तरीके अपनाए गए।

ONGC: एमसी को घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए 6 ई-कचरा रिक्शा प्रदान किए गए। इन रिक्शाओं ने स्वच्छता गीत भी बजाए।

DGH: स्वच्छता वार्ता, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता दीवार पेंटिंग और वृक्षारोपण अभियान उनके कार्यों के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान में सहयोग किया

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) को राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान के साथ चलने पर गर्व है, जिसका शुभारंभ माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा द्वारा 24 जून 2024 को किया गया जिनमें माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अनुप्रिया पटेल और श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों व केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और विकास भागीदार के प्रतिनिधि शामिल रहे। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान का लक्ष्य दो महीने की अवधि में व्यापक, बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से डायरिया से होने वाली बच्चों की मृत्यु को कम करना है।

प्रमुख फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं:

स्वास्थ्य अवसंरचनाओं को सुदृढ़ बनाना: स्वास्थ्य सुविधाओं का रखरखाव और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति (ओआरएस, जिंक) की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

स्वच्छ जल और स्वच्छता की पहुंच में सुधार: सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपायों और टिकाऊ प्रथाओं को लागू करना।

पोषण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना: दस्त संबंधी बीमारियों को रोकने के लिए कुपोषण से निपटना।

स्वच्छता शिक्षा को बढ़ावा देना: स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना और बच्चों को स्वच्छता के बारे में शिक्षित करना।

इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में "सुरक्षित जल और स्वच्छता" पर जागरूकता अभियान, **"स्वच्छ गांव, शुद्ध जल बेहतर कल" का शुभारंभ किया।** यह अभियान गांव और पंचायत स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित जल एवं स्वच्छता प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

और अधिक पढ़ने के लिए यहां **क्लिक करें**

शोध पत्रों के लिए सार आमंत्रित करना: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएमजी) चरण-II

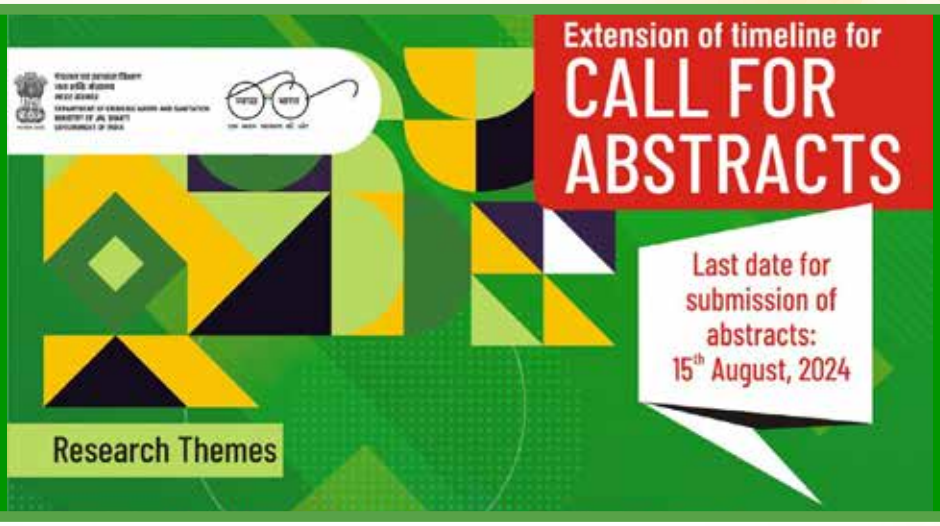

एसबीएम-जी विश्व स्तर पर सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में स्थान रखता है, जो जन-आंदोलन की शक्ति का प्रतीक है। इस महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी पहल द्वारा आर्थिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और सामाजिक लाभ प्रदान किए हैं, विशेष रूप से भारत की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा दिया गया है।

जैसे-जैसे हम एसबीएमजी के दूसरे चरण के अंतिम वर्ष में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य मार्च 2025 तक सभी गांवों के लिए 100% ओडीएफ प्लस मॉडल की स्थिति हासिल करना है। इस मिशन का समर्थन करने के लिए, हम राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, आरडब्ल्यूपीएफ भागीदारों, आईआईटी और चुनिंदा केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों से शोध पत्रों के लिए सार आमंत्रित करते हैं। यह एक राष्ट्रीय उद्देश्य में योगदान करने, एक प्रमुख मंच पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने और सार्थक बदलाव लाने का एक शानदार अवसर है।

सार प्रस्तुत करके इस पहल में भाग लेने से कई लाभ प्राप्त होंगे:

प्रभावशाली योगदान: शोध पत्र के लिए आपके सार सीधे ग्रामीण स्वच्छता नीतियों और प्रथाओं को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता में पर्याप्त सुधार हो सकता है।

राष्ट्रीय मान्यता: चयनित सारांशों से शोध पत्रों को राष्ट्रीय समारोह में प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिससे स्वच्छता के क्षेत्र में आपकी अंतर्दृष्टि को प्रदर्शित करने और मान्यता प्राप्त करने के लिए एक प्रतिष्ठित मंच उपलब्ध होगा।

सहयोगात्मक नेटवर्किंग: नीति निर्माताओं, साथी शोधकर्ताओं और प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़कर सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

सार प्रस्तुतीकरण: एसबीएम-जी आयामों (वर्टिकल) से संबंधित 3-5 शोध क्षेत्रों पर सार (लगभग 500 शब्द) पहचानें और प्रस्तुत करें। सार प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 15 अगस्त 2024 है।

मूल्यांकन के मानदंड:

- ग्रामीण स्वच्छता से प्रासंगिकता।
- मौलिकता और नवीनता।
- पद्धतिगत दृढ़ता।
- व्यावहारिक निहितार्थ और मापनीयता।

और अधिक पढ़ने के लिए यहां **क्लिक करें**

टिकाऊ अपशिष्ट समाधान के लिए गोवा की योजना: नवाचार और प्रगति

2 अक्टूबर, 2016 को स्थापित गोवा अपशिष्ट प्रबंधन निगम (GWMC) ने गोवा में अपशिष्ट प्रबंधन में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट प्रबंधन विभाग और ग्राम पंचायत के तहत इस विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) को ठोस और अन्य अपशिष्टों के वैज्ञानिक संग्रह, पृथक्करण, उपचार और निपटान का काम सौंपा गया है। अपशिष्ट मुद्दों को व्यापक रूप से समाधान करने के मिशन के साथ, GWMC ने नगरपालिका, बायोमेडिकल, खतरनाक, निर्माण और विध्वंस, और ई-कचरे सहित विभिन्न प्रकार के कचरे के प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत/ब्लॉक स्तर पर 14वें/15वें वित्त आयोग और SBM-G फंड के तहत स्थापित विभिन्न विकेंद्रीकृत सुविधाओं के अलावा कई केंद्रीकृत सुविधाएँ शुरू की हैं।

GWMC ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं स्थापित की हैं, जिससे कुशल और टिकाऊ अपशिष्ट उपचार सुनिश्चित होता है।

GWMC की पहल गोवा में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाती है। उन्नत सुविधाएँ स्थापित करके और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाकर, GWMC न केवल वर्तमान अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियों का समाधान कर रहा है, बल्कि एक स्वच्छ, हरित भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। ये प्रयास वैज्ञानिक और कुशल अपशिष्ट उपचार और निपटान के महत्व को रेखांकित करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।

और अधिक पढ़ने के लिए यहां **क्लिक करें**

एचडीएफसी बैंक-सीईई के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2024 समारोह : एक राष्ट्रव्यापी प्रयास

विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर, एचडीएफसी बैंक और पर्यावरण शिक्षा केंद्र (CEE) ने देश भर में नौ स्थानों पर "सूखे और प्लास्टिक कचरे से मुक्त ग्रामीण और शहरी परिदृश्य" का शुभारंभ किया। जल शक्ति मंत्रालय एवं स्वच्छ भारत मिशन टीमों द्वारा समर्थित, इस परियोजना ने प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए नगर निगमों, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरणों और कई सेवा प्रदाताओं को एकजुट किया।

अभियान की थीम, "हरित भविष्य की यात्रा" ने भूमि संरक्षण और व्यवहार्यता पर जोर दिया। 01 जून से 10 जून तक, एक राष्ट्रव्यापी ई-प्रतिज्ञा मंच ने नागरिकों को स्वच्छता प्रतिज्ञा लेने में सक्षम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप 5,345 शपथ हुईं। इस पहल से व्यापक पहुँच का प्रदर्शन हुआ, जिसमें तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और असम से अत्यधिक भागीदारी रही।

सामुदायिक सहभागिता: 6,150 से अधिक नागरिकों ने सफाई अभियान, रैलियों और वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। इन गतिविधियों ने लोगों को एकल-उपयोग प्लास्टिक को कम करने और जिम्मेदारीपूर्वक कचरे का निपटान करने की आदत डालने के लिए प्रेरित किया।

पर्यावरणीय प्रभाव: अभियान के तहत 37,226 मीट्रिक टन प्लास्टिक और सूखा कचरा एकत्र किया गया तथा 886 पौधे लगाए गए, जिससे भूमि पुनरुद्धार में योगदान मिला।

अभियान के परिणाम इसके व्यापक प्रभाव को दर्शाते हैं। ई-प्लेज अभियान 5,345 लोगों तक पहुंचा, जिससे जागरूकता बढ़ी और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहन मिला। विभिन्न क्षेत्रों में 580 SATO नल वितरित किए गए, जिससे जल संरक्षण और हाथ की स्वच्छता को बढ़ावा मिला।

और अधिक पढ़ने के लिए यहां **क्लिक करें**

एसबीएम ग्रामीण गुजरात ने ओडीएफ प्लस जागरूकता लाने के लिए राज्यव्यापी "शाला प्रवेश -उत्सव" का लाभ उठाया

गुजरात ने हाल ही में "शाला प्रवेश- उत्सव" मनाया, जो गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूलों के पुन: खुलने पर भव्य आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाते हुए, एसबीएम-जी (गुजरात) के द्वारा छात्रों और ग्रामीणों के बीच स्वच्छता और साफ-सफाई प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान शुरू किया।

शाला प्रवेश -उत्सव" के समानांतर चलाए गए इस अभियान में राज्य भर के 10,000 से अधिक स्कूलों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य छोटी उम्र से ही कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना था। यह पहल एक शानदार सफलता रही, जिसमें छात्र, शिक्षक और स्थानीय समुदाय स्थायी प्रथाओं का समर्थन करने के लिए एक साथ आए।

स्रोत पर पृथक्करण का प्रदर्शन: छात्रों ने अपशिष्ट पृथक्करण के व्यावहारिक प्रदर्शनों में भाग लिया। इन सत्रों का उद्देश्य छात्रों को बायोडिग्रेडेबल कचरे को गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे से अलग करने का महत्व सिखाना था। प्रदर्शनों का नेतृत्व प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और स्थानीय सफाई कर्मचारियों ने किया, जिन्होंने उचित कचरा प्रबंधन के दीर्घकालिक लाभों पर जोर दिया।

जागरूकता रैलियाँ: विभिन्न जिलों में 2,000 से अधिक जागरूकता रैलियाँ आयोजित की गईं। रंग-बिरंगे बैनर और पोस्टर लेकर छात्र अपने समुदायों में स्वच्छता और "प्लास्टिक मुक्त ग्राम" का संदेश फैलाने के लिए पैदल मार्च किया। ये रैलियाँ न केवल देखने लायक रहीं, बल्कि स्थानीय लोगों को अभियान में शामिल करने का एक शक्तिशाली साधन भी रहीं।

और अधिक पढ़ने के लिए यहां **क्लिक करें**

पश्चिम बंगाल में ओडीएफ स्थिरता के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना

स्वच्छता बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, पूरे पश्चिम बंगाल में 12,05,946 स्वयं सहायता समूह (SHG) 'व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (IHHL) की सुविधा प्रदान की जा रही है। 01 जुलाई से 15 अगस्त 2024 तक निर्धारित इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन एसएचजी के प्रत्येक सदस्य की शौचालय सुविधा तक पहुंच हो।

यह पहल महिलाओं को आवश्यक स्वच्छता बुनियादी ढांचा प्रदान करके उनके बीच स्वच्छता और गरिमा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस घोषणा के बाद, एसएचजी को संबंधित प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ उनकी उपलब्धि के लिए मान्यता दी जाएगी और लाभार्थी को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। एसएचजी एजेंडा में आईएचएचएल की पहुंच को एकीकृत करके, पश्चिम बंगाल न केवल स्वच्छता की मूलभूत आवश्यकता का समाधान करता है, बल्कि महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त भी बनाता है। यह अभियान न केवल स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है बल्कि सतत विकास को बढ़ावा देने में समुदाय संचालित पहल के महत्व को भी पुष्ट करता है।

और अधिक पढ़ने के लिए यहां **क्लिक करें**

कचरे को कंचन में बदलना: NADEP कंपोस्टिंग, छिंदवाड़ा , मध्य प्रदेश

कार्यालय ग्राम पंचायत देलाखारी

जनपद पंचायत तामिया , जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

दिनांक- 25 / 06/2024

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, हमारे ग्राम पंचायत में कुल 18 नाडेप बने है, सभी नाडेप खाद बनने हेतु भर दिये गये है। वरिष्ठ अधिकारी के भ्रमण के दौरान यदि कोई नाडेप खाली मिलता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी।

प्रमाणित किया सत्य है।

Certificate issued by Delakhari Gram Panchayat

Shramdan to fill NADEP by community members of Chhindwara district

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) चरण 2 ग्रामीण भारत में स्वच्छता में सुधार और कचरे का प्रबंधन करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) के अनुसार, भारत में सालाना 62 मिलियन टन से अधिक कचरा उत्पन्न होता है। इसमें से केवल 43 मीट्रिक टन कचरा एकत्र किया जाता है, 12 मीट्रिक टन निपटान से पहले शोधित किया जाता है, जिससे 31 मीट्रिक टन कचरा स्थल में छोड़ दिया जाता है। एसबीएम-जी चरण 2 का उद्देश्य गांवों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से निपटना है। मध्य प्रदेश में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एमपीपीसीबी द्वारा प्रस्तुत की गई 2019 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि राज्य में प्रति दिन लगभग 8,022.5 टन (TPD) कचरा उत्पन्न होता है, इसके अतिरिक्त, विश्व संसाधन संस्थान (WRI) जलवायु विश्लेषण संकेतक उपकरण (CAIT) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का GHG उत्सर्जन 1990 से 2014 तक 2,060 MtCO2e (180%) बढ़ा है।

अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं का समाधान करने के लिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले ने बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया है, जो दृश्य स्वच्छता, ग्राम स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में सुधार के एसबीएम-जी चरण 2 के लक्ष्यों के साथ संरेखित है। 784 ग्राम पंचायतों और 1,898 गांवों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है, जिसमें 8,507 एनएडीईपी खाद के गड्ढे शामिल हैं। तथापि, ज्ञान और उचित प्रथाओं की कमी के चलते इनमें से कई गड्ढों का दुरुपयोग सामुदायिक कूड़ेदान के रूप में किया गया था। इसे सुधारने के लिए, जिला कलेक्टर ने 1 मई से 30 जून, 2024 तक स्वच्छता अभियान शुरू किया।

कृषि विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि वह किसानों और समुदाय को खाद उत्पादन के लिए NADEP गड्ढों को भरने और तैयार करने के उचित तरीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करे। वरिष्ठ अधिकारियों को पंचायतों की देखरेख करने का काम सौंपा गया है ताकि दिशा-निर्देशों का उचित क्रियान्वयन और पालन सुनिश्चित किया जा सके।

और अधिक पढ़ने के लिए यहां **क्लिक करें**

महिला सशक्तिकरण: तेलंगाना के निर्मल जिले में मिशन RELA की यात्रा

मिशन RELA (ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और आजीविका सक्रियण) एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से निर्मल जिले में महिलाओं के जीवन को बदलना है।

मिशन RELA की शुरुआत: मिशन RELA का प्रस्ताव तेलंगाना के निर्मल जिले की जिला ग्रामीण विकास अधिकारी (DRDO) सुश्री के. विजयलक्ष्मी ने रखा था। ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए बेहतर मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन और आजीविका के अवसरों की ज़रूरत को समझते हुए, सुश्री के. विजयलक्ष्मी ने जिला कलेक्टर अभिलाषा अभिनव के सामने इस पहल को प्रस्तुत किया। इन्होंने उन्हें पूरा समर्थन और मार्गदर्शन दिया।

महत्वपूर्ण घटक

जागरूकता कार्यक्रम: पहले चरण में शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल था।

सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें: सैनिटरी पैड तक पहुँच की कमी को दूर करने के लिए, पूरे जिले में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में वेंडिंग मशीनें लगाई गईं। इन मशीनों का रखरखाव स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाता है, जिससे स्थिरता और स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित होती है।

सैनिटरी पैड निर्माण इकाई: कुंतला मंडल में एक विनिर्माण इकाई स्थापित की गई जिससे स्थानीय स्तर पर किफायती सैनिटरी पैड का उत्पादन शुरू हो सका है। यह इकाई न केवल आवश्यक उत्पाद उपलब्ध कराती है, बल्कि समुदाय की महिलाओं के लिए रोजगार भी सृजित करती है।

महुआ तेल इकाई: RELA के तहत महुआ तेल उत्पादन इकाई की स्थापना और ब्रांडिंग की गई, जिससे महिलाओं के लिए आय के अवसरों में और भी विविधता आई।

और अधिक पढ़ने के लिए यहां **क्लिक करें**

रांची, झारखंड में सूखे एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला

28 जून, 2024 को एसबीएम झारखंड ने रांची के अंगड़ा ब्लॉक में एक ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस पहल में डीआरडीए रांची, डीडब्ल्यू एंड एसडी रांची ईस्ट, एचडीएफसी बैंक, सीईई और नीड्स का सहयोग रहा। कार्यशाला में अंगड़ा और ओरमांझी से डीडीडब्ल्यूएस के ब्लॉक समन्वयक के साथ-साथ अंगड़ा के प्रमुख, अंगड़ा ब्लॉक के फेज-1 मुखिया, पंचायत सचिव , पंचायत समिति सदस्य और अन्य स्थानीय ब्लॉक अधिकारियों सहित 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

मुख्य विशेषताएं

परियोजना कार्य संबंधी प्रस्तुतिकरण: सीईई परियोजना अधिकारी ने ओरमांझी ब्लॉक में नवनिर्मित सामग्री संग्रहण सुविधा (एमआरएफ) को बनाए रखने के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हुए सूखे और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए परियोजनागत कार्यनीति पर प्रस्तुति दी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह एमआरएफ, जो इस क्षेत्र में पहला है, का लक्ष्य पांच महीनों में प्रति दिन लगभग 4-5 मीट्रिक टन का पृथक्करण शुरू करना है।

सामुदायिक सहभागिता: दो ब्लॉकों के 91 गांवों में लगभग 191 बैठकें आयोजित की गईं। हर घर में कचरे को अलग-अलग करने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न IEC गतिविधियाँ लागू की गईं। ध्यान सूखे और प्लास्टिक कचरे के संग्रह को अधिकतम करने और प्लास्टिक को जलाने और कूड़ेदान में फेंकने को कम करने पर था।

भण्डारण और पारंपरिक भस्मक बनाने पर चर्चा: श्री तरुण सिंह ने पंचायत संग्रहण केन्द्र में भण्डारण स्थान की पहचान करने और प्रत्येक पंचायत में भस्मक (पारंपरिक स्वच्छता भस्मक) बनाने के महत्व पर चर्चा की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आदर्श ग्राम पंचायत बनें।

और अधिक पढ़ने के लिए यहां **क्लिक करें**

राज्य के झरोखे से
झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्षेत्र में राज्य द्वारा किए गए प्रयास

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II, विभिन्न विभागों मुख्य रूप से पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास और आवास विभाग के साथ अभिसरण मोड के माध्यम से कार्य कर रहा है। अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से, गांव स्तर पर ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के लिए कार्यान्वियन का कार्य जारी है। गाँव में पारिवारिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्वच्छता, SLWM गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं और सामुदायिक संस्थाओं/ सार्वजनिक स्थानों को SLWM के माध्यम से कवर किया जाता है। सभी गाँवों में सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) पर विशेष रूप से स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में छात्रों और महिलाओं पर जोर देते हुए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही, सुरक्षित MHM प्रथाओं को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर भस्मक लगाए जा रहे हैं। SBM (G) चरण- II में, गाँवों को ODF प्लस श्रेणी में घोषित करने का प्रावधान है। व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर स्वच्छता पर ध्यान देने के अलावा, SHG, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों, शिक्षकों (पुरुष और महिला दोनों), स्वच्छाग्रहियों, पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधियों और अन्य जैसे विभिन्न हितधारकों के सहयोग से जागरूकता लाने संबंधी व्यापक अभियान चल रहा है।

जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशानुसार, एसएलडब्ल्यूएम हस्तक्षेपों के आधार पर 5-स्टार मॉडल गांव घोषित किए जाते हैं। एसबीएम जी के तहत निर्मित संरचनाओं की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए राज्य और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निगरानी दौरे किए जाते हैं। समुदायों को संरचनाओं के स्वयं संचालन और रखरखाव के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है। तदनुसार, स्थानीय/लाभार्थी समूहों की इसके लिए जिम्मेदारियाँ भी निर्धारित की जा रही हैं। ओडीएफ प्लस के संबंध में समुदाय को शिक्षित करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन और शारीरिक प्रशिक्षण साथ-साथ आयोजित किए जाते हैं ताकि कार्यक्रम के समय पर कार्यान्वियन के लिए उनका सहयोग प्राप्त हो सके। साथ ही, उन्हें एसबीएम अकादमी के माध्यम से ओडीएफ प्लस के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है यह अकादमी नियमित आधार पर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करती है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सभी लक्षित गांवों को 3 श्रेणियों में ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से स्वच्छता और एसएलडब्ल्यूएम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, आईईसी गतिविधियों के माध्यम से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वच्छता और एसएलडब्ल्यूएम से संबंधित संदेश प्रदर्शित किए जाते हैं।

जिला प्रशासन अक्सर उन ग्रामीणों को सम्मानित करता रहता है जिन्होंने एसबीएम जी में असाधारण योगदान दिया है। ओडीएफ प्लस स्थिरता संबंधी प्रयास जारी रखने के लिए, राज्य, जिलों और ब्लॉकों के सभी हितधारक हमेशा समुदाय को केंद्र में रखते हुए एकजुट होकर काम कर रहे हैं।

डॉ. नेहा अरोड़ा (आईएएस)
निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखंड.

निम्नलिखित को मिलाएं

1. उचित निपटान और पुनर्चक्रण के माध्यम से पर्यावरण पर प्लास्टिक कचरे के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से रणनीति	क. सामुदायिक भागीदारी
2. बेहतर स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए ग्रामीण समुदायों को शिक्षित करने और संगठित करने के लिए अभियान और जागरूकता कार्यक्रम	ख. सोख्ता गड्ढा
3. जब मलीय कचरे का शोधन स्थल पर ही किया जाता है	ग. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन
4. गंदले जल को सुरक्षित रूप से प्रबंधित किया जा सकता है	घ. कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना
5. पैकेजिंग और सेवा वस्तुओं में सामान्य	ङ. व्यवहार परिवर्तन
6. स्वास्थ्यकर स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के प्रति किसी व्यक्ति के कार्यों और दृष्टिकोण को प्रभावित करने की प्रक्रिया	च. सड़क निर्माण
7. हम ग्रामीण भारत में कचरा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं?	छ. एकल उपयोग प्लास्टिक
8. प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जा सकता है	ज. यथा स्थाने

उत्तर: 1-ग, 2-ख, 3-ज, 4-घ, 5-छ, 6-ङ, 7-च, 8-क

NIRDPR न्यूज़ लेटर

पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सचिव की कलम से

श्रीमती विनी महाजन,
सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय

"इस मिशन के अपने अंतिम वर्ष में, अपने प्रयासों को नई ऊर्जा प्रदान करना तथा सहयोग, रचनात्मकता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने के लिए कृत संकल्प हैं तथा जुलाई और अक्टूबर में हम विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करने जा रहे हैं ताकि देश भर में ओडीएफ प्लस मॉडल गांवों की घोषणा के कार्य में तेजी लाई जा सके।

इसके अतिरिक्त, हमने स्वच्छता और डायरिया की रोकथाम के बीच महत्वपूर्ण संबंध को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य किया। नियमित समीक्षा और सक्रिय भागीदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध रहें और उभरती चुनौतियों के प्रति उत्तरदायी रहें। इन सहभागिताओं को बढ़ावा देने और सजगतापूर्वक निगरानी बनाए रखकर, हमारा लक्ष्य ग्रामीण स्वच्छता और जन स्वास्थ्य के सुधार में स्थायित्व हासिल करना है।"

मिशन निदेशक की कलम से

श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक
(SBM-G), DDWS,
जल शक्ति मंत्रालय

"चूँकि हम अपने मिशन के 10वें वर्ष में आगे बढ़ रहे हैं, अत: हम अपनी प्रगति की निरंतर समीक्षा, संदर्भ और रिकॉर्ड के महत्व पर निरंतर जोर दे रहे हैं। यह दृष्टिकोण ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करता है और आगे की प्रगति के लिए आधार तैयार करता है। विभिन्न हितधारकों को ज्ञान में प्रभावी ढंग से अभिनवता लाने और उसे प्रबंधित करने, हमारी उपलब्धियों पर रचना करने और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमारा मिशन कृत संकल्प है।

वर्तमान में हम 'हर घर जल' और ओडीएफ प्लस मॉडल गांवों के प्रमाणीकरण के कार्य में तेजी लाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के साथ अपने सहयोग को लेकर अत्यधिक उत्साहित हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मिशन मोड में प्राथमिकता वाले अभियान सभी हितधारकों के सहयोगपरक प्रयासों और सक्रिय उपायों पर निर्भर करते हैं। दिनांक 22 से 26 जुलाई, 2024 और 2 अक्टूबर, 2024 को आयोजित की जाने वाली विशेष ग्राम सभाएँ कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रेरित करने और सहयोग देने के साथ-साथ, प्रभावशीलता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सामुदायिक निगरानी का कार्य भी शुरू करेंगी। "

स्वच्छता समाचार के अगले अंक में योगदान करने के लिए, हर महीने की 15 तारीख से पहले swachhbharat@gov.in पर अपनी प्रस्तुति साझा करें।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

विशेष सचिव का कार्यालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार।

चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
फोनः 011–24362192 | ईमेलः arun.baroka@nic.in